











## संपादकीय

## मुफ्त अनाज कितना जरूरी?

**प्रधानमंत्री** गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज दिसंबर के बाद भी एक साल तक मिलता रहेगा। कथित गरीबों के लिए एक और सुखद खबर है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल के तौर पर जो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा था, वह भी अब जनवरी, 2023 से एक साल तक 'बिल्कुल मुफ्त' बांटा जाएगा। सरकार के रिकॉर्ड में जो लोग 'गरीब' के तौर पर दर्ज हैं, उनकी बल्ले-बल्ले हो गई है। दरअसल भारत सरकार का यह सरोकार नहीं है कि मुफ्त अनाज के कितने लाभार्थी ऐसे गेहूं चावल को बाजार में बेच देते हैं, बेंकिंग उन्हें वह अनाज 'घटिया' लगाता है। मोदी सरकार अपना डाटा 'जनवादी' बनाए रखना चाहती है कि वह 81.35 करोड़ गरीब नागरिकों को बिल्कुल मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है। बेशक अर्थव्यवस्था पर इसके व्यापक विपरीत प्रभाव न पढ़ें और वित्तीय घाटा भी परिधियों के बाहर न हो, लेकिन कुछ सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि कोरोना-काल के बाद

मोदी सरकार अपना डाटा

‘जनवादी’ बनाए रखना चाहती है कि वह 81.35 करोड़ गरीब नागरिकों को बिल्कुल मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है। बेशक अर्थव्यवस्था पर इसके व्यापक विपरीत प्रभाव न पड़ें और वित्तीय घाटा भी परिधियों के बाहर न हो, लेकिन कुछ सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि कोरोना-काल के बाद आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने के बावजूद मुफ्त अनाज बांटते रहना क्या और क्यों जरूरी है? यदि 81 करोड़ से अधिक लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज, प्रति व्यक्ति प्रति माह, मुहैया नहीं कराया जाएगा, तो क्या वे भूखे मर जाएंगे।

लोगों में वितरित किया गया। बेशक आजकल कोरोना वायरस की वापसी की संभावनाएं और आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियां और उत्पादन बदल सूट जारी हैं, लिहाजा यह सवाल स्वाभाविक है कि सरकार कब तक मुफ्त अनाज बांटी रहेगी? कमोबेश पहले गरीबी और बेरोज़ागी का वैकल्पिक समाधान नहीं है। दरअसल यह मोदी सरकार का राजनीतिक तौर पर बेहद चतुर निर्णय है। बेशक भाजपा चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त अनाज मुहैया कराने का प्रचार करे या न करे, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर लोगों के मानस पर इसका प्रभाव रहता ही है। भाजपा कई चुनावों में इस फॉर्मूले को आजमा चुकी है। खासकर महिलाओं पर इस योजना का जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव देखा गया है, नतीजतन महांगाई, बेरोज़ागारी, किसानी, असंतोष, सांप्रदायिकता आदि मुद्दों के बावजूद भाजपा को जनादेश मिलता रहा है। 2023 में देश के 9 राज्यों में चुनाव हैं और अधिकतर राज्यों में भाजपा-एनडीए की सरकारें हैं। राजनीतिक तौर पर भाजपा के लिए अग्नि-परीक्षा से कम दौर नहीं होगा, क्योंकि वहीं के जनादेश से 2024 के आम चुनाव की पुष्टा जमीन तैयार हो सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने पारित कराया था। उसके तहत तीन-चौथाई ग्रामीण और लगभग आधी शहरी आबादी को सबसिडी पर अनाज हासिल करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ था। मोदी सरकार ने इसे व्यापकता दी है। अब सबसिडी पर ही नहीं, बल्कि बिल्कुल मुफ्त अनाज हासिल किया जा सकता है। योजनाओं से कितनी 'काली भेड़ें' जुड़ी हैं, यह एक अलग सवाल है और इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। अनाज का उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति माह जितना किया जाता है, कमोबेश 5 किलोग्राम अनाज से उसकी करीब आधी जरूरत पूरी हो जाती है। यह राष्ट्रीय सैंपल सर्वें का अभी तक का औसत डाटा है।

कुछ अलग

## ਬਦ ਫਪਤਰਾ ਕ ਆਗ

**हिमाचल** में पिछली सरकार के अंतिम चरण के फैसलों को वर्तमान की चुनौती में देखना जितना आवश्यक है, उतना ही लाजिमी है अर्थ गणित में प्रदेश की प्राथमिकताओं को गतिशील बनाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की मानें तो पिछली जयराम सरकार ने तीन हजार करोड़ की होली खेलते हुए, अपने रिवाज बदलने की कोशिश में आर्थिक स्थिति का मुंडन कर दिया। करीब 590 कार्यालयों की फैहरिस्त में अब जवाबदेही ढूँढ़ने का वक्त आया, तो इसे केवल राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ही बयों समझा जाए। यह भी मानना पड़ेगा कि नए संस्थानों की अधीि बारिश के बावजूद न कभी मिशन रिपीट हुआ और न ही इस बार रिवाज बदलने का संकल्प पूरा हुआ। भले ही विपक्ष कार्यालयों के डिनोटिफाइड होने को लेकर राज्यपाल तक पहुंच गया या आने वाले समय में इसको लेकर अदालती मंचन भी करे, लेकिन कहीं तो प्रदेश के लिए हमें सोचना ही पड़ेगा और इस बार यह दायित्व कांग्रेस सरकार का है। बात केवल 590 कार्यालयों के खोलने पर किए गए एतराज तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे यह फैसला लेने की दृढ़ता से पता चलेगा कि जनता को असती संदेश है क्या। सरकार को अगर वित्तीय अनुशासन कामयाब करना है, तो आरंभिक तौर पर पिछली सरकार के फैसले पलटना आसान होगा, मगर यह सवाल नीति-कृषि क्षेत्र से संबंधित मसाले का नि ति किया गया, उससे भारत ने मानव कल्याण के साथ बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की कमाई का नया अध्याय भी बनाया। 21वीं सदी में भी पारंपरिक इलाज के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे आयुर्वेद ने काफी विश्वसनीयता हासिल की है और इससे आयुर्वेदिक व्यापार उत्तम है। यह भी मैं 1

निर्देशों की बानी में भी देखा जाएगा, ताकि पता चले कि सुख्खु सरकार अपने तौर पर कितनी किफायत से प्रदेश को बचा रही है। यह सत्ता के लाभार्थी पदों पर नई नियुक्तियों, कार्यालयों के युक्तिकरण, अनावश्यक कार्यालयों पर कार्रवाई तथा विकास के समन्वय व प्रादेशिक संतुलन से ही सामने आएगा। प्रदेश में सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को प्रदर्शित करते सरकार के इरादे कार्य संस्कृति को कितना सशक्त करते हैं या सरकारी मशीनरी कितनी अनुशासित हो पाती है, यह देखना होगा। नई सरकार के लिए अपने पांच जमाने और कुछ नया कर दिखाने की भले ही चुनावी शर्त सबसे पहले सामने आ रही है।

जमाने और कुछ नया कर दिखाने की भले ही चुनावी शर्तें सबसे पहले सामने आ रही हैं, लेकिन स्थायी तौर पर इंस्टीच्यूट बिल्डिंग तथा संस्थानों व कार्यालयों के दायित्व निर्वहन में गुणवत्ता लाने की सबसे बड़ी चुनौती है। बहरहाल कार्यालयों की डिनोटिफिकेशन के तर्क कई अधूरे संकल्पों, अताकिंक फैसलों तथा राजनीतिक अनैतिकता की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में क्या वर्तमान सरकार उन तमाम कार्यालयों, संस्थानों, भवनों, विभागों, निगमों व बोर्डों को भी बंद करेगी, जो निरंतर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ही कमज़ोर कर रहे हैं। सरकारों के अनावश्यक नखरे तो समारोहों के आयोजन तथा सत्ता की परिपाठियों में भी नजर आते हैं, तो क्या हम समझें कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा जो अनावश्यक है। सरकार के कठोर फैसलों का स्वागत करने वालों की एक सूची है और इस लिहाज से, मंतव्य को जाहिर करने की ईमानदारी अगर सामने आती है, तो यह सोने पे सुहागा ही होगा। सरकार अगर एक नई परिपाठी के तहत फैसले लेने का सामर्थ्य रखती है, तो एक बार पिछली तमाम सरकारों के मंतव्य और गंतव्य को भी समझ लेना होगा, क्योंकि अब कई बदलाव आ चुके हैं और भविष्य की चुनौतियां भी सख्त हो रही हैं। सरकार को पिछली भाजपा सरकार की 'डबल इंजन' अवधारणा का जवाब खोजना है और साबित भी करना है कि राज्य अपने बूते स्वभिमान, आत्मनिर्भरता, कार्यप्रणाली और अपने आर्थिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। पहली डगर पर सबसे अहम होगा कि सुशासन की परिपाठी में अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और फिजूल खर्चियों से हटकर भविष्य के ग्रस्त खोजे जाएं।

डा. अश्विनी महाजन

१८

से आयात 68.46 अरब डालर थे, वहीं अब कर वर्ष 2022 के पहले नौ महीनों में 89.66 अरब डालर हो गए हैं। वर्ष 2021 के पूरे वर्ष में चीन से आयात 97.5 अरब डालर और अगर आयातों की यही गति जारी रही तो वे इस वर्ष 120 अरब डालर पहुंच जाएंगे। यूं तो आयात-निर्यात एक सामान्य क्रय है, लेकिन चीन से बढ़ते आयात इस कारण चिंता का सबब होते हैं, क्योंकि इससे व्यापार घटा बढ़ता है और देश की विदेशी को देनदारी भी। यदि देखा जाए तो इस वर्ष के पहले नौ महीनों में चीन को कुल निर्यात मात्र 13.97 अरब डालर के थे यानी 75.69 अरब डालर का व्यापार घटा। माना जा रहा है कि यह वर्ष पूर्ण होने पर चीन से व्यापार घटा 100 अरब डालर तक पहुंच सकता है, एक रिकार्ड होगा। गौरतलब है कि चीन से बढ़ते आयातों और के कारण भारत की चीन पर बढ़ती निर्भरता के महेनजर सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विभिन्न उपाय अपनाए। प्रथम 14 उद्योगों को चिन्हित किया गया, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, केंटक्स उपकरण, थोक दवाएं, टेलिकॉम उत्पाद, खाड़ी उत्पाद, एलईडी, उच्च क्षमता सोलर पौधों मॉड्यूल, ऑटोमोबाइल र औटो उपकरण, वस्त्र उत्पाद, विशेष स्टील, ड्रोन इत्यादि मेंल थे। बाद में सेमी कंडक्टर को भी इसमें जोड़ा गया। ये वो उपाय थे जो अधिकांशतः पिछले 20 वर्षों में चीन से बढ़ते आयातों के समक्ष प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने के कारण बंद हो गए थे अथवा बंदी के कारण पर थे। चीन के द्वारा हिंसक कीमतों पर डंपिंग, चीन कार की निर्यात सब्सिडी और तत्कालिक सरकार की वेदनशील नीति के तहत आयात शुल्कों में लगातार कमी ने आयातों को भारत में स्थान बनाने में सहयोग दिया। क्यों बढ़ते हैं चीन से आयात : आज जब भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य के तहत पीएलआई स्कीम, तकनीकी सहयोग और भन्न उपायों के माध्यम से बंद हो चुके अथवा बंदी के कागार पर उद्योगों को नया जीवन प्रदान करने की कोशिश कर रही है तो में क्या कारण है कि उसके बावजूद चीनी आयात बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो जा रहा है कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल नोनी एवं उसके कलपुर्जे और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात यक तेरी से बढ़ रहे हैं। सरकारी तरक्की यह है कि चूंकि चीन से



एक अच्छा संकेत है और देश में बढ़ते मैनुफैक्चरिंग की ओर इंगित करता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि देश में चीनी मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात पर मूल्य संवर्धन से देश में रोजगार का निर्माण भी होता है। यह भी कहा जाता है कि चूंकि चीन से मध्यवर्ती वस्तुएं सस्ते दामों पर आती हैं, इसलिए उत्पादन लागत भी कम हो जाती है। इस तर्क के आधार पर इकरियर और भूमंडलीकरण समर्थक अन्य आर्थिक संगठन चीन से बढ़ते आयातों को गलत न मानते हुए, बल्कि उन पर आयात शुल्क घटाकर उन्हें और ज्यादा बढ़ावा देने की पैरवाई करते हैं। गौरतलब है कि देश में चीनी साजोसामान के भारी विरोध के बावजूद जो चीनी आयात बढ़ रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि चीन से आने वाले आयातों का एक बड़ा हिस्सा तैयार उपभोक्ता वस्तुओं का नहीं, बल्कि मशीनरी और रसायन समेत अन्य मध्यवर्ती वस्तुओं का है। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह इन मध्यवर्ती वस्तुएं बनाने का सामग्र्य भारत में नहीं है? शायद यह सही नहीं है। एक देश जो अंतरिक्ष, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल, मिसाइल समेत कई क्षेत्रों में सुपर पावर है, वो जीरो टेक्नॉलॉजी की मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं बना सकता, यह समझ के परे है। समझना होगा कि चीन द्वारा सस्ते माल की डिपिंग और कई अन्य अनुचित हथकंडे अपना कर भारत में क्षमता निर्माण को बाधित किया गया है, और यह घट्यंत्र रुक नहीं रहा है। कहा जाता है कि व्यापार एक युद्ध है और उसे उसी प्रकार से संचालित किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट यानी ऐपीआई का एक ज्वलंत उदाहरण है। आज से 20 वर्ष पूर्व हमारी ऐपीआई

आवश्यकताओं की 90 प्रतिशत आपूर्ति भारत ही होती थी, जबकि चीन और अन्य देशों को डिपिंग के कारण एपीआई उद्योग नष्ट हुआ और आज एपीआई की 90 प्रतिशत आपूर्ति आयातों से होती है। हमारे द्वा उद्योग की इतनी बड़ी निर्भरता केवल अर्थिक ही नहीं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो रही है। मात्र पीएलआई ही नहीं, सरकार को अन्य उपाय भी अपनाने होंगे, ताकि भविष्य में चीनी आयात फिर से नए बन रहे एपीआई उद्योग को नष्ट न कर सके। यहां संवाल केवल चीन से आने वाले प्रत्यक्ष आयातों का ही नहीं है। देश में बड़ी मात्रा में चीनी आयात विभिन्न आसियान देशों के माध्यम से भी होकर आ रहे हैं। गौरतलब है कि भारत का आसियान देशों से मुक्त व्यापार समझौता है, जिसके तहत शून्य आयात शुल्क पर अधिकांश आयात आ जाते हैं। मूल देश की शर्त लगातार जब चीनी आयातों को रोका गया तो चीनी कंपनियों ने अपनी फैक्टरियां आसियान देशों में ही लगा ली, जिसके कारण उन्हें चीनी बताकर रोका नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त भारत में कार्यरत कई विदेशी आटोमोबाइल कंपनियां भी कलपुर्जे विदेशों से मंगा रही हैं। जब भारत ने मोबाइल फोन पर आयात शुल्क बढ़ाए तो कई विदेशी कंपनियों ने भारत में मैन्यूफैक्चरिंग प्रारंभ कर दी। लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में कलपुर्जे चीन समेत अन्य देशों से मंगा एंजा रहे हैं और हजारों वर्षों से कपड़ा उद्योग भारत का एक बड़ा उद्योग है और पिछले 100 सालों में आधुनिक कपड़ा उद्योग का भी विकास देखने को मिलता है। भारत वस्त्र एवं परिधान हेतु कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता रखता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें भी विदेशों से भारी आयात होते हैं। उदाहरण के लिए, चीन से कपड़ा आयात 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 46.2 प्रतिशत अधिक था, जिससे कपड़ा क्षेत्र में क्षमता का बहुत कम उपयोग हो रहा है। गौरतलब है कि पिछले एक वर्ष में चीन से आने वाले अधिकांश प्रकार के आयात चाहे वो रसायन हो, प्लास्टिक का सामान हो, वस्त्र हो, मशीनरी हो, पहले से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। एक तरफ सरकार द्वारा पीएलआई स्कीम के तहत भारी खर्च कर उन उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है, जो चीन से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण नष्ट हो गए थे अथवा अत्यधिक रूप से प्रभावित हुए।

# कोरोना में आयुर्वेद के लिए अवसर

इस समय जहां चान का काहराम मचा रह काराना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन बीएफ.7 की वजह से बड़ी संख्या में मौत के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं यह वायरस अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत तहित कई देशों में दस्तक दे चुका है। चीन सहित दुनियाभर में कोरोना संक्रमण से बचाव करने वाली दवाइयों की भारी कमी हो रही है और इनकी कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। ऐसे में एक बार फिर दुनिया में भारत की कोरोना रोधी आयुर्वेदिक दवाइयों व मसालों की नई मांग निर्मित होते हुए दिखाई दे रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोरोनाकाल में आयुर्वेदिक सेक्टर की अहमियत बढ़ने के साथ-साथ आयुर्वेदिक बाजार तेजी से बढ़ा है। कोविड-19 की नुस्खायों के बीच आयुर्वेदिक बाजार को तेजी से आगे बढ़ाने हेतु सरकार प्रयास सरत रही है। निःसंदेह कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के दौरान भारत के सदियों पुराने आयुर्वेद को दुनिया भर में अपनाया गया है। भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के यासों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक संघटकों के उपयोग की सफल रणनीति बनाकर इसके नियांत बढ़ाए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक कोरोनाकाल में भारत के द्वारा जिस तरह दुनिया के 150 से अधिक देशों को आयुर्वेदिक दवाइयों और कृषि क्षेत्र से संबंधित मसालों का नियांत केया गया, उससे भारत ने मानव कल्याण के साथ बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की कमाई का नया अध्याय भी बनाया। 21वीं सदी में यी पारंपरिक इलाज के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब रहे आयुर्वेद ने काफी विश्वसनीयता हासिल की है और इससे आयुर्वेदिक बाजार बढ़ा है। हाल ही में 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9वें विश्व आयुर्वेद कंग्रेस (डब्ल्यूएसी) के समापन समारोह और तीन राष्ट्रीय आयुष संस्थानों के उद्घाटन समारोह में कहा कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए नहीं है। आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत में आयुष के क्षेत्र में करीब 40 हजार सूक्ष्म, लघु और प्रथम (एमएसएमई) उद्योग कार्यरर हैं जो अनेक विविध डोडकट दे रहे हैं। इनसे लोकल इकॉनमी को बड़ी ताकत मिल रही है। आठ साल पहले देश में आयुष इंडस्ट्री करीब-करीब 20 हजार करोड़ रुपए के आसपास ही थी। आज आयुष इंडस्ट्री करीब-करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। ऐसे में आगामी वर्ष 2023 से आईटी की तरह भारत के आयुर्वेदिक बाजार में भी तेजी से विस्तारित होने और इसके विदेशी मुद्रा की कमाई का नया तेजी से बढ़ता माध्यम बनने की नुकसनदेह संभावनाएं उभरकर दिखाई दे रही हैं। निःसंदेह केंद्र सरकार आयुर्वेद सहित पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को अतिसिक्रियता के साथ वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ी है। सरकार ने 50 से अधिक देशों के साथ आयुर्वेद सहित पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ाने से संबंधित अनुसंधान विकास और शिक्षण-प्रशिक्षण के विभिन्न समझौता जापानों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 13 नवंबर 2020 को पांचवें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर वेश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएसओ) के महानिदेशक टेड़स अधानोम थेरेसस ने भारत में पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना सुनिश्चित की है। इसका उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों में परंपरागत और पूरक दवाओं के अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को मजबूत किया जाना है। निश्चित रूप से इस समय जब डब्ल्यूएसओ ने भारत में पारंपरिक दवाओं

दक दवाइयों के बाजार के बढ़ना का नई समावेश एवं बढ़ा में अब आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार को देश और दुनिया से बढ़ाने के लिए कई बातों पर ध्यान देना होगा। हमें मान्य से आयुर्वेदिक दवाइयों के दस्तावेजीकरण की डगर पर ढाना होगा। हमारे द्वारा औषधीय पौधों को रासायनिक शरों के इस्तेमाल से पूरी तरह मुक्त रखा जाना होगा। अब के निर्माण में भारी तत्वों का इस्तेमाल रोकना होगा। अब के द्वारा आयुर्वेद के नाम पर फूड प्रोडक्ट और अन्य का कारोबार करने वाले लोगों पर सरकत निपाहे रखी गयी। सरकार के द्वारा ऐसे नए नियम बनाए जाने होंगे ताकि डटक की जो कंपनियां अपने ब्रांड को आयुर्वेदिक बता करती हैं, उनके दावों की जांच हो सके। चूंकि भारत दुनिया में यजड़ी-बृद्धियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और इसे लगार्डन ऑफ दि वल्ड यानी विश्व का वनस्पति उद्यान बताता है। ऐसे में देश में औषधीय गुणों से भरपूर सैकड़ों तरह दवाओं के अधिकतम उत्पादन की नई रणनीति बनाई जानी में आयुर्वेदिक दवाइयों के बाजार को बढ़ाने के लिए कई तत्वों पर भी ध्यान देना होगा। भारतीय औषध प्रणाली के भी औषधीय पौधों की समृच्छ बॉटनिकल पहचान करनी होगी। औषधीय पौधों की प्रोसेसिंग वैज्ञानिक, और सुरक्षित तरीके से की जानी होगी। आयुर्वेदिक की क्षमता और सुरक्षा का निर्धारण करने के लिए लैलोजिकल तथा क्लीनिकल अध्ययन बढ़ाया जाना आयुर्वेदिक दवाओं के लिए उपयुक्त नियमन व्यवस्था बताती की जानी होगा। आयुर्वेदिक इलाज की प्रक्रियाओं का तय किया जाना होगा। यह ध्यान रखा जाना होगा कि देक आहार प्रोडक्ट की लेबलिंग, प्रेजेंटेशन और विज्ञापन नयां अनुचित रूप से यह गारंटी नहीं दे सके कि उनका किसी बीमारी के पूर्ण इलाज या उसे रोकने में पूर्णतया है। यह भी ध्यान रखा जाना होगा कि आयुर्वेदिक दवाएं, देक पद्धति पर बनी अन्य दवाएं, मेडिसिन प्रोडक्ट और द्य सामग्री जिसमें आयुर्वेदिक तत्वों का इस्तेमाल न हुआ आयुर्वेद उत्पादों के दायरे में नहीं आ पाएं। साथ ही देक प्रोडक्ट में सिर्फ नेचुरल फूड एंडिटिव ही मिलाए आयुर्वेदिक आहार में अनुपयुक्त रूप से विटामिन, मिनरल मेंने एसिड मिलाने की इजाजत नहीं हो। यह भी ध्यान ना होगा कि आयुर्वेदिक आहार बनाने वाली कंपनियां डटक के पैकेट पर ऐसा कोई दावा नहीं करें जिससे ग्राहकों ग्राहकों को भ्रमित किए जाने संबंधी जांच होने पर कोई नकलती है तो कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई लगती की जानी होगी। कोई आहार या आयुर्वेद दवा कंपनी बीमारी को रोकने का दावा करती है तो इसके लिए सुरक्षा के तहत पहले प्रोडक्ट की जांच कराकर लेबलिंग की या सुनिश्चित की जानी होगी। आयुर्वेदिक आहार प्रोडक्ट पर उपयुक्त जानकारी सुनिश्चित जानी होगी। हम करें कि अब देश का आयुर्वेदिक बाजार तेजी से आगे और देश में आईटी की तरह आयुर्वेद सेक्टर से विदेशी मुद्रा कीली कमाई को भी मुश्कियों में लिया जा सकेगा। हम करें कि कोरोना वायरस के नए वैरिएट ऑमिक्रोन और अन्य नए कोरोना वायरस के कारण देश में निर्मित रोधी आयुर्वेदिक दवाइयां और मसाले फिर से दुनिया में संकरण रोकने और लोगों के स्वास्थ्य कल्पणा में अहम बदलाव लाएं।

## जाष पर बाज़ पर बायजूद बना रहा भरोसा

### चीनी

कैलेंडर के हिसाब से 2022 बाध का वर्ष था। हिम्मत और हौसले का साल। सच मानें, तो यह पूरा साल हर मोर्चे पर हिम्मत और हौसले का इम्तिहान ही लेता रहा। साल खत्म होते होते यूंलग रहा है, मानो सामने से भरी एक बड़ी खाई आ गई है, अब इसे पार करने के लिए छलांग लगानी है या पानी कम होने का इंतजार करना है? यह सबाल भारत की ही नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ा है। इसकी बजह यह है कि कोरोना महामारी के प्रकोप से निकलने की भविष्यवाणी के साथ शुरू हुआ साल खत्म होते होते नसिर्क उस उम्मीद पर पानी फेर चुका है, बल्कि एक नई चिंता भी पैदा हो गई है कि क्या हम 1970 के दशक जैसे गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़े हैं, जहां आर्थिक तरकीकी कछुए की चाल पर पहुंच जाए और महंगाई खरोश की रफतार से कुलांचे भरती दिखाई पड़े। यह चिंता विश्व बैंक के 'इकोनॉमिक आउटलुक' में जाती हुई है। विश्व बैंक की चिंता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर है। उसका अनुमान है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुई महंगाई पूरी दुनिया को भारी पड़नेवाली है। विश्व बैंक को लगता है कि इस साल दुनिया की जीडीपी में 2.9 फीसदी की वृद्धि ही हो पाएगी। हालांकि, भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक का भरोसा कायम है। न सिर्फ कायम है, बल्कि उसे लगता है कि दुनिया भर में मंदी की चिंता व आशंका के बीच भारत ही है, जो सबसे अच्छी तरह इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। विश्व बैंक का अनुमान था कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी 6.5 प्रतिशत बढ़ेगी, पर ताजा रिपोर्ट में उसने यह अनुमान बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है। भारतीय बाजार में घरेलू मांग मजबूत रहेगी और इसके दम पर ही भारत दुनिया की तेजी से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्थाओं में एक रहेगा। उम्मीदों के बावजूद इस साल की सबसे बड़ी मुसीबत महंगाई ही रही। जनवरी में एक बार महंगाई का आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक की बदर्शत की सीमा, यानी छह प्रतिशत के पार हुआ, तो फिर केंद्रीय बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे 11 महीने बाद नवंबर में ही यह बदर्शत के दायरे में लौट पाया। फिर भी यह मानने के एक से ज्यादा कारण है कि कोरोना महामारी की चेपेट में दो साल बर्बाद होने के बाद कम से कम इस साल कुछ तो ऐसा हुआ कि साल खत्म होने पर चैन की सांस ली जा सके। महंगाई काबू में आती दिख रही है।

देशदुनिया से

जब पर बोझ के बावजूद  
बना रहा भरोसा

**चीनी** कैलेंडर के हिसाब से 2022 बाघ का वर्ष था। हिमत और हौसले का साल। सच मानें, तो यह पूरा साल हर मोर्चे पर हिमत और हौसले का इम्तिहान ही लेता रहा। साल खत्म होते-होते युंग रहा है, मानो सामने किरण पानी से भरी एक बड़ी खाँई आगई है, अब इस पार करने के लिए छलांग लगानी है या पानी कम होने का इंतजार करना है? यह सवाल भारत की ही नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ा है। इसकी वजह यह है कि कोरोना महामारी के प्रकोप से निकलने की भविष्यवाणी के साथ शुरू हुआ साल खत्म होते-होते नसिर्फ उस उम्मीद पर पानी फेर चुका है, बल्कि एक नई चिंता भी पैदा हो गई है कि क्या हम 1970 के दशक जैसे गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़े हैं, जबां आर्थिक तंत्रिकी के द्वारा जीवन और पर्यावरण का रूपांतरण हो रहा था।

जहा जावेक तरकना कछुएका बाल पर भुजे जाए जा महान् खरारा  
की रफ्तार से कुलांचे भरती दिखाई पड़े। यह चिंता विश्व बैंक के  
‘इकोनॉमिक आउटलुक’ में जरूरी गई है। विश्व बैंक की चिंता पूरी दुनिया  
की अर्थव्यवस्था को लेकर है। उसका अनुमान है कि युक्रेन पर रूस के  
हमले से पैदा हुई महार्घी पूरी दुनिया को भारी पड़ेवाली है। विश्व बैंक को  
लगता है कि इस साल दुनिया की जीडीपी में 2.9 फीसदी की वृद्धि ही हो  
पाएगी। हालांकि, भारत की  
अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक का  भ्रोसा कायम है। न सिर्फ  
कायम है, बल्कि उसे लगता है  
कि दुनिया भर में मंदी की चिंता

वा आशंका के बीच भारत ही है, जो सबसे अच्छी तरह इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। विश्व बैंक का अनुमान था कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी 6.5 प्रतिशत बढ़ेगी, पर ताजा रिपोर्ट में उसने यह अनुमान बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है। भारतीय बाजार में घेरेलू मांग मजबूत रहेगी और इसके दम पर ही भारत दुनिया की तेजी से बढ़नेवाली फीसदी की वृद्धि ही हो पाएगी। हालांकि, भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक का भरोसा कायम है। न सिर्फ कायम है, बल्कि उसे लगता है कि दुनिया भर में मंदी की चिंता व आशंका के बीच भारत ही है, जो सबसे अच्छी तरह इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकता है। विश्व बैंक का अनुमान था कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी 6.5 प्रतिशत बढ़ेगी, पर ताजा रिपोर्ट

अर्थव्यवस्थाओं में एक रहेगा। उम्मीदों के बावजूद इस साल की सबसे बड़ी मुसीबत महंगाई ही रही। जनवरी में एक बार महंगाई का आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक की वर्दानश्त की सीमा, यानी छह प्रतिशत के पार हुआ, तो फिर केंद्रीय बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे 11 महीने बाद नवंबर में ही यह वर्दानश्त के दायरे में लौट पाया। फिर भी यह मानने के एक सेज्यादा कारण हैं कि कोरोना महामारी की चपेट में दो साल बर्बाद होने के बाद कम से कम इस साल कुछ तो ऐसा हुआ कि साल खत्म होने पर चैन की सांस ली जा सके। महंगाई का बाकू में आती दिख रही है।

मैं उसने यह अनुमान बढ़ाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया है। भारतीय बाजार में घरेलू मांग मजबूत रहेगी और इसके दम पर ही भारत दुनिया की तेजी से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्थाओं में एक रहेगा। उम्मीदों के बावजूद इस साल की सबसे बड़ी मुसीबत महंगाई ही रही।

यूकून और रूप युद्ध से पैदा हुई तमाम परेशानियों के बावजूद अब ऐसा लग रहा है कि जिंदगी पटरी पर लौट सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था में रफ्तार लौटती दिख रही है और कंपनियों की बैलेस्स शीट तो यूं दिखती है, जैसे उनको कोई बूस्टर खुराक लग गई हो। महीने-दर-महीने जीएपटी वसूली का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है और आयकर के मोर्चे पर भी खुशखबरी ही आ रही है। इसी का असर है कि वित्त मंत्री ने जब संसद में बजट के 3,25,756 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव रखा, तो सवालों के जवाब में उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इस रकम को जुटाने के लिए सरकार कोई नया कर्ज नहीं लेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सात महीनों में ही पिछले साल के मुकाबले कर वसूली में 18 प्रतिशत की बढ़ोतारी हुई है, जो उन्हें भरोसा देती है कि सरकार को अपने खर्च के लिए जरूरी पैसा मिल जाएगा। दरअसल, इस साल एक पुराना सबक याद आया है कि सारी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज खर्च बढ़ाना ही है। 1970 के दशक की जिस मंदी के लौटने की आशंका विश्व बैंक को सता रही है, उसका इलाज इसी तरह खर्च में जोरदार बढ़त के साथ ही किया गया था। अब भारत को देखें, तो पिछले साल के और उससे पहले के आंकड़े भी सबवाल उठाते हैं कि आम आदमी का खर्च तो बढ़ रहा है, सरकार भी कुछ खर्च बड़ा रही है, लेकिन बड़े उद्योगों को जितना निवेश करना चाहिए, वह क्यों नहीं हो रहा है? सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि साल के शुरुआती नौ महीनों में औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों में 25 प्रतिशत की कमी आई है।



## सौंदर्य

## स्किन टैग को खत्म करें ये टिप्प



शरीर या चेहरे के किसी हिस्से पर मौजूद स्किन टैग, तिल, लैकेंडहेड्स, स्पॉट और मस्से आपकी सुंदरता को बिगड़ा देते हैं। बढ़ती उम्र के साथ-साथ इनकी गिरावट भी बढ़ती जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सी लड़कियां सर्जरी या महोर ब्यूटी शैटमेंट का सहारा लेती हैं लेकिन इसका अच्छा उत्तर दिखाने की बाजे एक साइड-इफेक्ट्स नज़ारे आने लगते हैं। लोकन अगर सही मनी मैनेजमेंट के साथ ही थोड़ी सी ट्रांसपरेंसी भी रखता जाए, तो रिस्ता अच्छा होगा।

**मस्से:-** मस्से की समस्याओं को दूर करने के लिए एक सोकड़ बैंडेज पर



एप्पल साइडर सिरका लगाकर हफ्ते में 2 बार मस्से पर लगाएं। इसके बाद पिंप्स स्टेन की मदद से इसे निकाल दें। 1 हफ्ते में ही आपको मस्से से छुटकारा मिल जाएगा।

**स्किन टैग:-** काँटन की मदद से लगातार दिन में 2 स्किन टैग पर एप्पल साइडर दिखाने की तरफ लगाएं। लगातार 10 दिन तक इसे लागाने से स्किन टैग छड़ा जाएं।

**तिल:-** अनवांछि तिल से छुटकारा पाने के लिए दिन में 4 घंटे रोजाना



लहसुन पीस कर लगाएं। कुछ ही दिनों में तिल गायब हो जाएगे।

**ब्लैकहेड्स:-** ब्लैकहेड्स को दूर करने के लिए चेहरे पर स्टीम लेकर 5 मिनट तक शहद लगा लें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से थोके कर सफाकरें। रोजाना 1 हफ्ते तक इसका इत्यनांत ब्लैकहेड्स के लिए गायब कर दें।

**स्पॉट:-** ब्लैक स्पॉट के लिए नींबू के रस को रोजाना चेहरे पर लगाएं। नेचुरल ब्लैक की तरह काप करने वाला नींबू के रस आपको चेहरे के भद्दे स्पॉट से छुटकारा मिल जाएगा।

## जीपीएस सिग्नल में आ रही समस्या का करें समाधान

आप घर से निकलने के साथ ही पूरा पता और नक्षा आपने फोन पर सर्च कर लेते हैं, जिससे कि आपका फोन हर छोटे-बड़े जगह से चोरा हो जाता है। यह सिर्फ जीपीएस तकनीक का डेवलपर्स नहीं है, जो लोकेशन सर्विस का उपयोग करते हैं। ऐसे में यदि जीपीएस सिग्नल में थोड़ी भी परेशानी हो, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जानिए, कैसे जीपीएस सिग्नल को बेहतर किया जा सकता है।

## क्या है जीपीएस

जीपीएस का आशय है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यह तकनीक आपकी उपस्थिति को बताता है और जैसे-आज कहाँ हैं और कहाँ एक एप्लिकेशन हैं, जो लोकेशन सर्विस का उपयोग करते हैं। ऐसे में यदि जीपीएस सिग्नल में थोड़ी भी परेशानी हो, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जानिए, जीपीएस को बेहतर किया जा सकता है।

## पता करें जीपीएस की परेशानी

यदि आपके फोन के जीपीएस में कोई भी समस्या हो, तो उसका भी पता लगा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए फोन में जीपीएस



इसेसे जीपीएस में समस्या कमज़ोर सिग्नल की चाया गया था। वर्ष 1973 में अमेरिकन अर्मी ने इसे नींबू के लिए बनाया था, लेकिन 1995 में इसके सेवा को शिकायत से इतर प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

## जीपीएस डाटा को करें रिफेंश

कभी-कभी सेटेलाइट सिग्नल न होने की वजह से यह फोन को रोक रहा है। इसका मौलिक बहुत है, जो सिर्फ फोन के लिए लागत होती है।

ट्रूलॉक्स जैसे एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये फोन के जीपीएस डाटा को बिल्यूर कर देते हैं फिर से सेटेलाइट से कनेक्ट करने में सक्षम बनाते हैं।

## लाई प्लॉटरी सोड से हटाए

कई बार लोग फोन में बैटरी की खपत को कम करने के लिए जीपीएस सिग्नल को हाई एप्क्यूरेसी मोड से हटा देते हैं। बैटरी बचाने के लिए तो यह सही है, लेकिन इससे कभी-कभी जीपीएस स्टॉक जानकारी नहीं देता। यदि कभी लाकेंप सर्च के दौरान आपको लगता है कि जीपीएस सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है, तो हाई एप्क्यूरेसी को उपरी कंपनी के लिए उपलब्ध कराएं।

## स्टार्टफोन में जीपीएस

स्पार्टन में जीपीएस के लिए एक सेंसर लगा होता है। यह सेंसर अंतर्वित जीपीएस से कम्प्युटरकेशन कर आपकी उपस्थिति को बताता है। इस सेंसर को फोन में लगा अब हाईवेयर और साप्टवेयर द्वारा कटौल किया जाता है। ऐसे कभी-कभी जीपीएस सिग्नल में समस्या आ जाती है।

## ऐसे बनाएं

एक चम्चल लौंग को पहले खुरदूरा पीस लें, फिर एक कप पानी में इसे डालकर पानी से 10 मिनट तक उबालें। जब पानी उबालने लगे तो आधा चम्चल चाय की थोड़ी गति होने पर लौंग की चाय पीना काफी फायदेमंद होता है। इससे आपको काफी फायदा होता है।

4. पाचन संबंधी समस्याओं में लौंग की चाय अप्रकार के हैं। घंटे में रसिंघड़ी होने और पाचन तंत्र की थोड़ी गति होने पर लौंग की चाय पीना काफी फायदेमंद होता है। इससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करता है।

5. दांतों में दर्द होने पर अक्सर लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लौंग की चाय भी इसके लिए फायदेमंद हो सकती है।

3. शरीर के अंगों और मांस पेशीयों में होने वाले दर्द से निजात पाना चाहते हैं तो लौंग की चाय जरूर पिए। इसके अलावा आप आप चाहें तो लौंग की चाय से दर्द वाले स्थान की सिर्काई कर सकते हैं। इससे आपको काफी फायदा होता है।

4. पाचन संबंधी समस्याओं में लौंग की चाय अप्रकार है। घंटे में रसिंघड़ी होने और पाचन तंत्र की थोड़ी गति होने पर लौंग की चाय पीना काफी फायदेमंद होता है। इससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करता है।

5. लौंग की चाय पीना काफी फायदेमंद होता है। इसका प्रयोग करने से आपका बुखार अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा।

3. शरीर के अंगों और मांस पेशीयों में होने वाले दर्द से कार्य जरूर करते हैं। इसके अलावा आप आप चाहें तो लौंग की चाय से दर्द वाले स्थान की सिर्काई कर सकते हैं। इससे आपको काफी फायदा होता है।

4. पाचन संबंधी समस्याओं में लौंग की चाय अप्रकार है। घंटे में रसिंघड़ी होने और पाचन तंत्र की थोड़ी गति होने पर लौंग की चाय पीना काफी फायदेमंद होता है। इससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करता है।

5. दांतों में दर्द होने पर अक्सर लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लौंग की चाय भी इसके लिए फायदेमंद हो सकती है।

3. दांतों में दर्द होने पर अक्सर लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लौंग की चाय भी इसके लिए फायदेमंद हो सकती है।

4. पाचन संबंधी समस्याओं में लौंग की चाय अप्रकार है। घंटे में रसिंघड़ी होने और पाचन तंत्र की थोड़ी गति होने पर लौंग की चाय पीना काफी फायदेमंद होता है। इससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करता है।

5. दांतों में दर्द होने पर अक्सर लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लौंग की चाय भी इसके लिए फायदेमंद हो सकती है।

3. दांतों में दर्द होने पर अक्सर लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लौंग की चाय भी इसके लिए फायदेमंद हो सकती है।

4. पाचन संबंधी समस्याओं में लौंग की चाय अप्रकार है। घंटे में रसिंघड़ी होने और पाचन तंत्र की थोड़ी गति होने पर लौंग की चाय पीना काफी फायदेमंद होता है। इससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करता है।

5. दांतों में दर्द होने पर अक्सर लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लौंग की चाय भी इसके लिए फायदेमंद हो सकती है।

3. दांतों में दर्द होने पर अक्सर लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लौंग की चाय भी इसके लिए फायदेमंद हो सकती है।

4. पाचन संबंधी समस्याओं में लौंग की चाय अप्रकार है। घंटे में रसिंघड़ी होने और पाचन तंत्र की थोड़ी गति होने पर लौंग की चाय पीना काफी फायदेमंद होता है। इससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करता है।

5. दांतों में दर्द होने पर अक्सर लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लौंग की चाय भी इसके लिए फायदेमंद हो सकती है।

3. दांतों में दर्द होने पर अक्सर लौंग के तेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लौंग की चाय भी इसके लिए फायदेमंद हो सकती है।

4. पाचन संबंधी समस्याओं में लौंग की चाय अप्रकार है। घंटे में रसिंघड़ी होने और पाचन तंत्र की थोड़ी गति होने पर लौंग की चाय पीना काफी फायदेमंद होता है। इससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करता है।</